



वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report 2004-05





अ.प्र.नि. द्वारा प्रधान मंत्री को रु.1 करोड़ का चेक जोकि कर्मचारियों द्वारा एक दिन के वेतन का अंशदान है और रु.2 करोड़ का चेक जोकि बैंक का अंशदान है सुनामी पीड़ितों के लिए प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत निधि के लिए सौंप रहे हैं।

CMD handing over cheques to Prime Minister for Rs.1 crore being the contribution of a day's salary by employees and for Rs.2 crore being the Bank's contribution to the Prime Minister's National Relief Fund for Tsunami victims



एम.बी.एन. राव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

MBN Rao
Chairman & Managing Director

निदेशकों की रिपोर्ट 2004-2005

ए.सी.नीलसन-ओआरजी मार्ग द्वारा दिसंबर 2004 में किए गए एक सर्वेक्षण में अच्छी सेवाओं के कारण बैंक लगातार दूसरे वर्ष भी लोगों की दृष्टि में प्रमुख दक्षिण स्थित सेवा ब्रांड के रूप में सामने आया है।

वर्ष 2004-05 के दौरान रु. 958.07 करोड़ का परिचालन लाभ दर्ज करते हुए इसने पूँजी पर्याप्तता एवं विभिन्न अन्य वित्तीय अनुपातों में पर्याप्त मात्रा में सुधार किया है। बैंक का कारोबार रु.53,000 करोड़ के आँकड़े को पार कर गया।

इंडियन बैंक के निदेशक मण्डल को बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के साथ 31 मार्च 2005 तक के लेखा परीक्षित तुलनपत्र तथा 31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखे को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

निदेशक मंडल, बैंक के समस्त सम्मानित ग्राहकों से मिलने वाले अमूल्य सहयोग के लिए अपना आभार और कृतज्ञता प्रकट करता है। निदेशक मंडल, स्टाफ सदस्यों के महत्वपूर्ण योगदान की भी सराहना करता है। मानव संसाधनों और उन्नत प्रौद्योगिकी का उत्तम प्रयोग करते हुए बैंक देश में सर्वश्रेष्ठ बैंकों में से एक बनने का लक्ष्य रखता है।

निदेशक मण्डल के लिए
और उनकी ओर से

एम बी एन राव

एम बी एन राव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रधान कार्यालय, चेन्नै

12 मई 2005

Directors' Report 2004 - 05

The Bank emerged in the public eye as the foremost south based service brand consecutively for the second time, in a survey conducted by A.C.Nielsen-ORG-MARG in December, 2004.

During 2004-05, the Bank has shown an impressive performance by recording an operating profit of Rs.958.07 Crore. It has substantially improved the Capital Adequacy and various other Financial Ratios. The Business of the Bank crossed the Rs.53,000 Crore mark.

The Board of Directors of the Bank are pleased to present the Annual Report of the Bank together with audited Balance Sheet as on March 31, 2005 and Profit & Loss Account for the year ended March 31, 2005.

The Board places on record its appreciation and gratitude for the valuable patronage of all the esteemed customers of the Bank. The Board also appreciates the members of staff for their significant contribution. The Bank aims at becoming one among the Best Banks in the country by synergising the best use of skilled Human Resources and upgraded Technology.

For and on behalf of the

Board of Directors

MBN RAO

Chairman & Managing Director

Head Office,

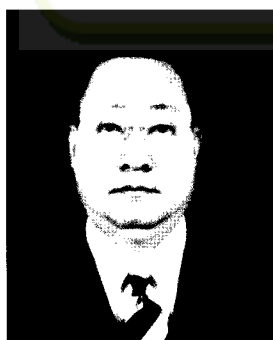
Chennai 12th May, 2005

कार्यपालक निदेशक
Executive Director

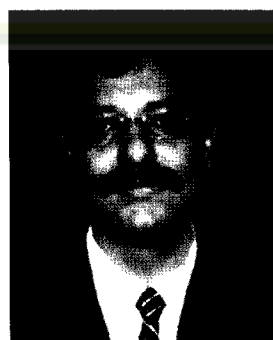


बी. साम्बमूर्ति
B. SAMBAMURTHY

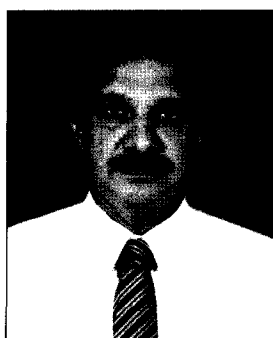
निदेशक / Directors



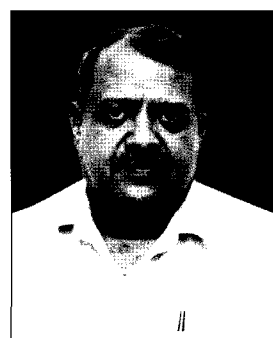
राम मोयवा
RAM MUIVAH



डॉ. रबी एन. मिश्र
DR. RABI N MISHRA



ए. एस. जॉर्ज
A.X. GEORGE



अशोक गुप्ता
ASHOK GUPTA

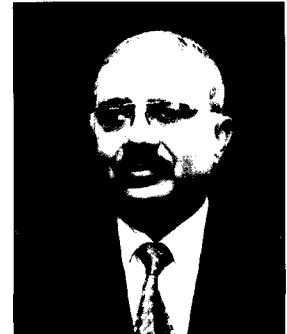
महा प्रबंधक / General Managers



एस अरुणाचलम
S. ARUNACHALAM



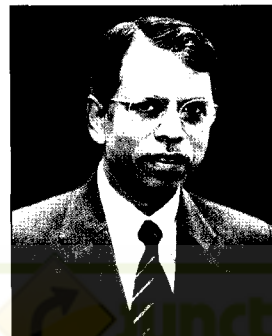
डॉ. जयन्ती लाल जैन
Dr. JAYANTI LAL JAIN



टी. वल्लियप्पन
T. VALLIAPPAN



वी. संतानरामन
V. SANTHANARAMAN



एस. आर. शिवस्वामी
S.R. SHIVASWAMY



वी. श्रीनिवासन
V. SRINIVASAN



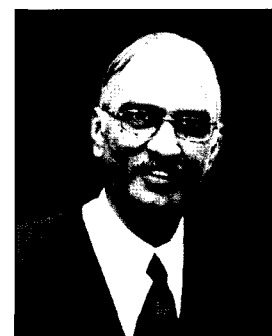
कृष्णमूर्ति कोटा
KRISHNA MURTHY KOTA



एस के विर्मानि
S.K. VERMANI



एस. सूर्यनारायणन
S. SURYANARAYANAN



सी.एस. रमणी
C.S. RAMANI

महा प्रबंधक / General Managers



ए विश्वनाथन
A. VISWANATHAN



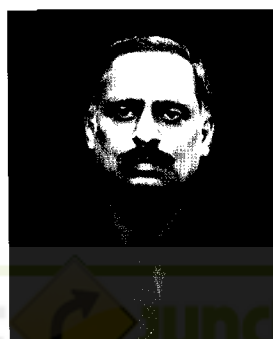
जग मोहन गर्ग
JAG MOHAN GARG



आर रामचन्द्रन
R. RAMACHANDRAN



के बी नागेन्द्र मूर्ति
K.B. NAGENDRA MURTHY



के एम गोपीनाथ
K.M. GOPINATH



सी गजपतिराजन
C. GAJAPATHIRAJAN



पी आर बालसुब्रमणियम
P.R. BALASUBRAMANIAM



आर विजयराम राव
R. VIJAYA RAMA RAO



सदानन्द मिश्र
SADANAND MISRA



जे वी सुब्रमण्यम
J.V. SUBRAHMANYAM

भारतीय अर्थव्यवस्था

अंतर्देशीय गतिविधियाँ

• भारतीय अर्थ व्यवस्था में 2003-04 में 8.5 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2004-05 में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान किया गया है। औद्योगिक उत्थान में दृढ़ता और विस्तीर्णता आई जो मुख्य रूप से निर्माण और निर्यात में तेजी के कारण हुआ। सेवा क्षेत्र ही इस वृद्धि का प्रमुख आधार रहा है। प्रतिकूल मानसून के बावजूद भी कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में सकल देशी उत्पाद की वृद्धि में 1.1 प्रतिशत बढ़ावा हुआ है तथा खाद्यान्न का उत्पादन 210 मिलियन टन से अधिक रहा।

• 2004-05 के प्रथम ग्यारह महीनों में औद्योगिक उत्पादन की सूची (आईआईपी) में पिछले वर्ष में इसी अवधि के दौरान 6.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 8.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। औद्योगिक क्षेत्र की समग्र वृद्धि में 89.8 प्रतिशत का योगदान करते हुए उत्पादन क्षेत्र ने उच्चतम वृद्धि दर्ज की है। विद्युत के उत्पादन में तीव्रता दर्ज हुई जबकि खनन क्षेत्र में उत्पादन में थोड़ी-सी कमी आयी।

• 2004-05 के पहले वर्षाब्द में बढ़ने के बाद वर्ष की समाप्ति में मुद्रास्फीति संयत हुई है। तेल, खनिज और धातुओं के वृद्धिशील अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति के क्षेत्र में आपूर्ति की ओर से दबाव प्रबल रहा। 2003-04 और 2002-03 में क्रमशः 5.4 प्रतिशत और 3.4 प्रतिशत से 2004-05 के दौरान औसत डबल्यू पी आई पर आधारित मुद्रास्फीति की दर 6.4 प्रतिशत बन गई थी।

• मुद्रा की आपूर्ति (एम₃) में 2003-04 के 16.9 प्रतिशत के विरुद्ध 2004-05 में 12.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2004-05 के लिए आकलित किया गया है कि सकल

INDIAN ECONOMY

Domestic Developments

• The Indian economy is estimated to have grown at 6.9 percent for the year 2004-05 on top of 8.5 percent growth for 2003-04. The industrial recovery firmed up and broadened, driven mainly by manufacturing and buoyant exports. The services sector remained the main engine of growth. Despite unfavourable monsoons, the GDP growth in agriculture and allied activities rose by 1.1 percent with food grains production at over 210 million tonnes.

• The Index of Industrial Production (IIP) grew by 8.1 percent during the first eleven months of 2004-05, as against 6.9 percent for the corresponding period of last year. The manufacturing sector recorded the highest growth with a contribution of 89.8 per cent to the overall growth of the industrial sector. Electricity generated recorded a faster expansion while the output in the mining sector declined marginally.

• Inflation has moderated by the end of 2004-05 after rising in the first half of the year. Supply side pressures dominated the inflation scenario driven by a hardening of international prices of oil, minerals and metals. The average WPI-based inflation rate accelerated to 6.4 per cent during 2004-05 from 5.4 per cent and 3.4 per cent during 2003-04 and 2002-03 respectively.

• Money supply (M₃) increased by 12.8 per cent during 2004-05 as compared to 16.9 per cent for 2003-04. The Gross Fiscal Deficit of

राजकोषीय घाटा रु.1,39,231 करोड रहेगा जो सकल देशी उत्पाद का 4.5 प्रतिशत है ।

बाहरी गतिविधियाँ

• 2004-05 के प्रथम ग्यारह महीनों में यूएस डालर में आकलित देश के व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में पिछले वर्ष में इसी अवधि के दौरान 16.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 27.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा 2004-05 के पहले ग्यारह महीनों में कच्चा तेल के अन्तर्राष्ट्रीय दामों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप तेल के आयात में 44.6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी से डालर में आकलित आयात में 36.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । 2003-04 में 28.8 प्रतिशत की तुलना में तेल से इतर आयातों के मूल्य में 2004-05 के दौरान 33.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । पिछले वर्ष में 13.7 बिलियन यूएस डालर की तुलना में इस वर्ष में व्यापार घाटा 23.8 बिलियन यूएस डालर (फरवरी 2005 तक) बन गया ।

• 2004-05 के दौरान रुपए का विनिमय मूल्य प्रति यूएस डालर के लिए रु.43.36- 46.46 की विस्तार सीमा में था, जोकि 2004 में मार्च की समाप्ति के स्तर से 0.7 प्रतिशत का मूल्यह्रास दिखाता है । पाउंड स्टर्लिंग और यूरो के विरुद्ध क्रमशः रुपये का मूल्यह्रास 3.0 प्रतिशत और 6.0 प्रतिशत रहा । मार्च 31, 2005 को देश की विदेशी विनिमय आरक्षितियाँ, 141.5 बिलियन यूएस डालर रहीं ।

2005-06 के लिए भावी संभावनाएँ

• 2005-06 के दौरान प्रक्षेपित किया गया है कि वास्तविक जीडीपी की वृद्धि 7.0 प्रतिशत होगी । यह प्रक्षेपित किया गया है कि मुद्रास्फीति की दर 5.0-5.5 प्रतिशत की विस्तार सीमा में होगी तथा यह तेल के क्षेत्र में उसके सार्वभौमिक दाम और अंतर्देशीय आमेहन में बढ़ते अनिश्चय के अद्यधीन होगी । जीडीपी की वास्तविक वृद्धि और मुद्रास्फीति के समनुरूप मुद्रा आपूर्ति(एम 3) में प्रक्षेपित विस्तार, 14.5 प्रतिशत होगा ।

Central Govt. is estimated at Rs.1,39,231 Crore for 2004-05, which is 4.5 percent of GDP.

External Developments

• The country's merchandise exports in US Dollar terms grew by 27.1 per cent during the first eleven months of 2004-05 as compared to 16.4 per cent for the corresponding period of 2003-04 while imports in US Dollar terms grew strongly by 36.4 per cent for the first eleven months of 2004-05 mainly due to a surge in oil imports by 44.6 per cent following a rise in international crude oil prices. The value of non-oil imports increased by 33.3 per cent during the first eleven months of 2004-05 as compared to 28.8 per cent during the corresponding period of 2003-04. The trade deficit widened to US\$ 23.8 billion (up to Feb. 2005) as compared with US\$ 13.7 billion in the previous year.

• During 2004-05, the rupee moved in the range of Rs. 43.36-46.46 per US Dollar, depreciating by 0.7 per cent over its end-March 2004 level. The rupee depreciated against Pound Sterling and Euro by 3.0 per cent and 6.0 per cent respectively. The country's foreign exchange reserves stood at 141.5 billion US Dollar as on March 31, 2005.

Outlook for 2005-06

• During 2005-06, the real GDP growth is projected at around 7.0 percent. Inflation rate is projected to be in the range of 5.0-5.5 percent subject to the growing uncertainties on the oil front both in regard to global prices and their domestic absorption. Consistent with the real growth of GDP and inflation, the projected expansion of money supply (M3) would be 14.5 per cent. The aggregate deposit of

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाओं में 15.0 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने की अपेक्षा की गई है। एसएलआर से इतर निवेशों सहित गैर-खाद्य बैंक ऋण में 19.0 प्रतिशत की वृद्धि प्रक्षेपित की गई है जिससे अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक क्षेत्रों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

मुद्रा नीति और बैंकिंग में परिवर्धन

- 2004-05 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के वार्षिक नीति विवरण का रुख था कि ऋण में वृद्धि के लिए पर्याप्त नकदी प्रदान की जाए और अर्थव्यवस्था में निवेश और निर्यात की मांग को सहायता दी जाए तथा वृद्धि की गति को बनाये रखने के लिए अनुकूलतम ब्याज दर की परिस्थिति का निर्वाह किया जाए।

- बैंक दर और पुनः खरीद दर अपरिवर्तित थीं। प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में दो चरणों में 50 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोत्तरी करते हुए 5 प्रतिशत तक बढ़ाया गया, अर्थात् सितंबर 18, 2004 से 25 बीपीएस बढ़ाये गये तथा अक्टूबर 2, 2004 से 25 बीपीएस और बढ़ाये गये। सीआरआर पर ब्याज दर को बैंक दर (6 प्रतिशत) से घटाकर 3.5 प्रतिशत कर दिया गया।

- मौद्रिक नीति के मध्यावधि पुनरीक्षण में बैंक नीति को अपरिवर्तित रखा गया। भारतीय रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत अक्टूबर 27, 2004 के प्रभाव से नियत पुनः खरीद दर में 25 बेसिस प्वाइंट बढ़ाकर उसे 4.75 प्रतिशत बनाया गया। अक्टूबर 29, 2004 के प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग के अनुरूप रीपो और रिवर्स रीपो शब्दों का परस्पर परिवर्तन किया गया।

- बैंकों को सलाह दी गई कि वे उधारकर्ताओं के लिए व्यापक और सख्त जोखिम निर्धारण बनाने के लिए कदम उठावें ताकि ऋण का मूल्य निर्धारण, और उचित रूप से जोखिम के साथ मेल खाये।

scheduled commercial banks is expected to grow at over 15.0 per cent. Non-food bank credit including non-SLR investments of banks is projected to increase by around 19.0 per cent to meet the credit needs of all the productive sectors of the economy.

Developments in Monetary Policy and Banking

- The stance of the Annual Policy Statement of Reserve Bank of India for 2004-05 was to provide adequate liquidity to meet credit growth and support investment and export demand in the economy and to pursue an interest rate environment conducive to maintaining the momentum of growth.

- The Bank rate and the repo rate remained unchanged. The cash reserve ratio (CRR) was hiked by 50 bps in two stages to 5 per cent, i.e., by 25 bps from the fortnight beginning September 18, 2004 and 25 bps points from October 2, 2004. The interest rate on CRR was reduced to 3.5 per cent from the Bank Rate (6 per cent).

- In the Mid-term review of the Monetary Policy, the Bank rate was kept unchanged. The fixed repo rate was increased by 25 basis points under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) of RBI effective from October 27, 2004 to 4.75 per cent. The terms 'repo' and 'reverse repo' were interchanged with effect from October 29, 2004 in tune with the international usage of these terms.

- Banks were advised to take steps for putting in place comprehensive and rigorous risk assessment of borrowers so that the pricing of credit is related to risk more appropriately.

• बैंकों को मूलभूत संरचना क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक अवधि की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि वाले अपने ऋणों की सीमा तक 5 वर्ष की न्यूनतम परिपक्वता के दीर्घ-कालीन बाण्ड जारी करने की अनुमति दी गयी ।

• बेसल II मानदण्डों में बाधाविहीन बदलाव सुनिश्चित करने हेतु प्रस्ताव किया गया कि बाज़ार जोखिम हेतु पूँजी प्रभार के कार्यान्वयन को 31 मार्च, 2006 को समाप्त होनेवाली दो वर्षों की अवधि तक चरणबद्ध बनाये जाएं और बैंक बेसल II के अन्तर्गत उपलब्ध विकल्पों का गहन अध्ययन करें । बेसल II में बदलाव के लिए बैंक दिसंबर 2004 तक एक नक्शा बनाएँ तथा उसके बाद तिमाही अंतरालों में प्रगति की पुनरीक्षा करें ।

• एनपीए की आयु के अनुसार, जिन खातों को मार्च 31, 2005 के प्रभाव से "तीन वर्षों से अधिक अवधि के लिए संदिग्ध" के संवर्ग में शामिल किया गया है, के लिए अधिक प्रावधान करने की आवश्यकता है ।

• बैंकों को सलाह दी गयी है कि नए खाते खोलने में वे अपने बोर्ड द्वारा अपनायी गयी 'अपने ग्राहक को जानिये' (के वाई सी) नीति का पूर्ण अनुपालन करें और के वाई सी के प्रयोजनों के लिए प्राप्त की गयी जानकारी का प्रयोग, उत्पादों के 'क्रास-सेल्लिंग' जैसे प्रयोजनों के लिए न किया जाए ।

• मीयादी जमाओं की अवधि में एकरूपता प्रदान करने के उद्देश्य से बैंकों को अपनी व्यक्तिगत अंतर्देशीय सावधि जमाओं (रु.15लाख से कम) की न्यूनतम अवधि को 15 दिनों से 7 दिनों में घटाने की अनुमति प्रदान की गयी । रु.15 लाख और उससे अधिक राशि की थोक सावधि जमाओं पर विभेदक ब्याज दर उपलब्ध कराने की स्वतंत्रता जारी रखी गयी ।

• सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों को छोड़कर बाकी सभी कार्यक्रमों पर सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के प्रतिबंधात्मक प्रावधान हटा दिये गये हैं । व्यास समिति की संस्तुति

• Banks were allowed to raise long-term bonds with a minimum maturity of 5 years to the extent of their exposure of residual maturity of more than 5 years to the infrastructure sector.

• With a view to ensuring smooth transition to the Basel II norms, it was proposed to phase the implementation of capital charge for market risk over a two-year period ending March 31, 2006 and that the banks should examine in-depth the options available under Basel II. Banks were to draw a road map by end December 2004 for migration to Basel II and review the progress thereof at quarterly intervals.

• Higher provisioning was required according to the age of NPAs, which are included under 'doubtful for more than three years' category, with effect from March 31, 2005.

• Banks have been advised to fully adhere to the Know Your Customer (KYC) policy adopted by their Boards for opening new accounts and that information collected for KYC purposes should not be used for any other purpose such as cross-selling of products.

• In order to provide uniformity in the tenor of term deposits, banks were allowed to reduce the minimum tenor of retail domestic term deposits (under Rs. 15 lakh) from 15 days to 7 days. The freedom of offering differential interest rates on wholesale term deposits of Rs. 15 lakh and above was continued.

• The restrictive provisions of Service Area Approach were dispensed with except for government-sponsored programmes. As